


दिनांक...१३-५-२३...का परा ना

12-04-2023 पत्रावली आज पेश हुई। वकील पार्थी व पैरोकर सरकार उपस्थित।

उभय की प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान कृषि अधिनियम 1955 पर बहस सुनी गयी। वकील पार्थी पैरोकर सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संस्था-01 ने ग्राम जाजोता की वादग्रस्त आराजी खान 913/633 रकबा 03-02-15 बीघा में से 06-00 बीघा भूमि पर अवैध रूप से बजरी का खनन किया है। अप्रार्थी का उक्त कार्य कृषि भूमि का अकृषि कार्य करने की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी ने बिना किसी सख्त स्वीकृति के कृषि भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग किया है जो धारा-133 राजस्थान कृषि अधिनियम 1955 के अंतर्गत अवैध है। अतः पार्थी ने प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। वकील अप्रार्थी-01 ने वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से बजरी का अवैध खनन नहीं किया है और ना ही मौके पर किसी प्रकार के गड्ढे हैं। अतः पार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।



उभय पक्ष वकील व पैरोकर सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दुसरीया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय शक्ति पार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः उक्त उपरोक्त विवेचन, बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर पार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान कृषि अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैलल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

विर्णय आज दिनांक 12-04-2023 को मेरे द्वारा  जाकर सरे- इजलास सुनाया गया।

12-04-23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)